

2025

5 मई - 18 मई

www.mukhiyajee.com

बिहार

पटना

वर्ष : 02 | अंक : 56/57

मुखियाजी

EVENING E-PAPER by APP World Media



सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज 20 पिनक एवं 166 डीलक्स बसों के परिचालन का किया लोकार्पण। मौके पर अन्य मंत्री व अधिकारी रहे मौजूद।



वो साल दूसरा था
ये साल दूसरा है

पाकिस्तान के तब
हुए थे दो टुकड़े

अबकी सीज फायर ने
सब 'गड़बड़' कर दिया

अमेरिका के दबाव से
हर भारतीय हतप्रभ

पाक के सीजफायर पर
किसी को भरोसा नहीं

लोगों को बरबस ही याद
आ रही हैं इंदिरा गांधी

भा रत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसकी पहल किसने की; इस पर लंबी



बहस चल रही है। दोनों देश की सेनाओं ने इसे लेकर प्रेस ब्रीफिंग की। पाकिस्तान में तो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसी रात 'राष्ट्र के नाम संदेश' भी जारी किया। दोनों ही देश अपनी-अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि भारत ने पाकिस्तान के कई कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया।

अपनी
बात

पहलगायम से शुरू हुई यह आतंकी घटना 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पहुंच गया। इसी ऑपरेशन के तहत भारत ने 6-7 मई की रात में पाकिस्तान में

9 आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला किया। इस हमले से भारत को न केवल देश के अंदर जनता का भरपूर समर्थन मिला, बल्कि विश्व पटल पर तमाम देशों का नैतिक समर्थन मिला। केवल चीन और तुर्की का सपोर्ट पाकिस्तान को मिला, वह भी कूटनीतिक सपोर्ट। भारत सरकार के अनुसार, पाकिस्तान ने ड्रोन से 400 से अधिक हमले किये। 36 से अधिक शहरों को निशाना बनाया। सारे हमलों का भारतीय सेना ने सधी हुई रणनीति से सटीक और संयमित ढंग से जवाब दिया। इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। पूरा

विपक्ष भारत सरकार के साथ था। विपक्ष में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने स्पष्ट कहा कि वे सब देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों के समर्थन में हैं। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में भारत सही और संयमित ढंग से आगे बढ़ रहा था। वह किसी भी देश को बोलने का मौका नहीं दे रहा था। भारतीय सेना को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा था। 10 मई की दोपहर तक तो सबकुछ ठीक-ठाक रहा। अपराह्न बाद अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर आए पोस्ट ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि भारत-पाक उनके कहने पर सीजफायर को तैयार हो गया है। घंटा भर भी नहीं हुआ होगा कि भारत सरकार

ने भी सीजफायर की घोषणा कर दी। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर सरकार के प्रति गुस्सा चरम पर देखने को मिलने लगा। क्या बुद्धिजीवी, क्या अनपढ़, क्या युवा, क्या बुजुर्ग... सब नाराज। उनका गुस्सा इसके प्रति नहीं था कि युद्ध थम गया, बल्कि गुस्सा इसके लिए था कि अमेरिका के कहने पर भारत झुक गया। कूटनीतिक जीत में अमेरिका की पीठ पर सवार होकर पाकिस्तान भी बाजी मार ले गया। लेकिन, लोग तो यही कह रहे हैं कि यह सीजफायर नहीं है, बल्कि भारत के फायर (जीत) को अमेरिका ने अपनी साजिश से सीज (जब्त) कर लिया। हालांकि अब ट्रंप में अपने नए बयान में कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं करायी है।

(संबंधित खबर 71/25 पढ़ें पेज 06 पर)

2025

5 मई - 18 मई

www.mukhiyajee.com

बिहार

पटना

वर्ष : 02 | अंक : 56/57

मुखियाजी

EVENING E-PAPER by APP World Media



राहुल गांधी ने बिहार में आकर जातीय जनगणना पर नरेंद्र मोदी को घेरा, कहा- FIR मेरे लिए मेडल है... खबर पढ़ने के लिए QR Code स्कैन करें...

नया

नयी नाव की तरह राजनीति के मंझधार में उतारे जा रहे हैं निशांत कुमार, क्या कहते हैं सियासी पंडित

समाजवाद

Rajesh Thakur @ Patna

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 फरवरी 2022 को बड़ा बयान आया था। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा था- 'राममनोहर लोहिया तथा जॉर्ज फर्नांडिस के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सच्चे समाजवादी

हैं। आपने कभी नीतीश कुमार के किसी परिवार को कहीं राजनीति में देखा है क्या? समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी भी अपने स्वजनों को राजनीति में लाने पर जोड़ नहीं दिया। इसी तरह, बिहार व केंद्र में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इस सिद्धांत का पालन किया है और सही मायने में वह सच्चे समाजवादी

नेता हैं। नीतीश कुमार हमलोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वह सही अर्थों में समाजवादी हैं। कहीं नजर नहीं आते हैं उनके काम में उनके परिजन...' इस बयान के लगभग 3 साल बाद आज उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार के साथ पूरे देश के सियासी गलियारे में तेज बहस हो रही है।



शहर से गांव तक एक ही चर्चा

निशांत कुमार। यह नाम कुछ माह से बिहार के सियासी गलियारे में 'हॉट केक' बना हुआ है। पटना से लेकर राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में इस नाम पर खूब चर्चा हो रही है। शहर से लेकर गांव-मुहल्ले तक और चाय दुकानों से लेकर खेत-खलिहानों तक यह अघोषित मुद्दा बना हुआ है। जैसे तो निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की चर्चा गाहे-बगाहे पहले भी कभी-कभार हुई थी, लेकिन इसके लिए न तो नीतीश कुमार तैयार थे और न ही निशांत कुमार को ही राजनीति में कोई इंटरैस्ट था। जनता भी इसे गंभीरता से नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल के अंत से एक बार फिर इसे लेकर तेज चर्चा शुरू हुई

है। इस बार यह चर्चा जदयू खेमे से निकलकर बिहार के सियासी गलियारे में पहुंच गयी। मीडिया हाउस पहले इसे ट्रायल के रूप में लिया, बाद में इस पर गंभीरता से रिपोर्ट बनाने लगे। मुखियाजी के डिजिटल एडिशन ने भी इसे प्रमुखता से छापा था। जहां तक निशांत के राजनीति में आने की बात है तो इससे इनकार करने वाले दिग्गज सियासी पंडित भी अब मानने लगे हैं कि निशांत कुमार की बिहार पॉलिटिक्स में अघोषित रूप से एंट्री हो चुकी है। बस जनता को इसकी घोषणा का इंतजार है। उनके राजनीति में कदम रखने के जदयू कार्यालय से लेकर शहरों में लगे पोस्टरों और बैनरों से जहां संकेत मिलने

लगे थे, वहीं होली के मौके पर निशांत की आयी तस्वीर और 9 वर्षों के बाद उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास में होली के आयोजन से उस पर अघोषित रूप से मुहर लग गयी। अब तो निशांत कुमार के बयान भी मीडिया में आने लगे हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि उनके आने की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। किस बात की देर है। इस पर सियासी पंडितों का मानना है कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तैयार नहीं हैं। वहीं कुछ राजनीतिज्ञ का कहना है कि सियासी मंझधार में नयी नाव की तरह निशांत कुमार को धीरे-धीरे उतारा जा रहा है।

विस्तृत पेज 4





PARTH LIBRARY



Under Guidance of : **Dr. Shivendu Alok (G.S GURU)**

Our Features:

- 24x7 Study Environment.
- Positive & Peaceful Environment of Self Study.
- Comfortable Furniture for Long Hours Study.
- Wi-Fi Facility with High Speed.
- Fully Air Conditioned.
- CCTV Surveillance.
- Mineral Water.
- Locker Facility
- Power Backup & Charging Point
- Important Magazines & NewsPapers
- Reserved Seat for Girls



Admission
Open



Special Feature :

Free

Weekly Current Affairs Test
& Discussion

Dr. Shivendu Alok
(G.S. GURU)

Add: 2nd floor, Parth Civil Services

**धराहरा कोठी, सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया के पीछे, नया टोला-पटना-4**

9852550786
8083237786

मुखियाजी इंपेपर



मिथिलेश कुमार राय
अध्यक्ष

पहली वर्षगांठ
पर पूरी टीम को
हार्दिक बधाई

प्रदेश मुखिया संघ, बिहार

मुखियाजी इंपेपर

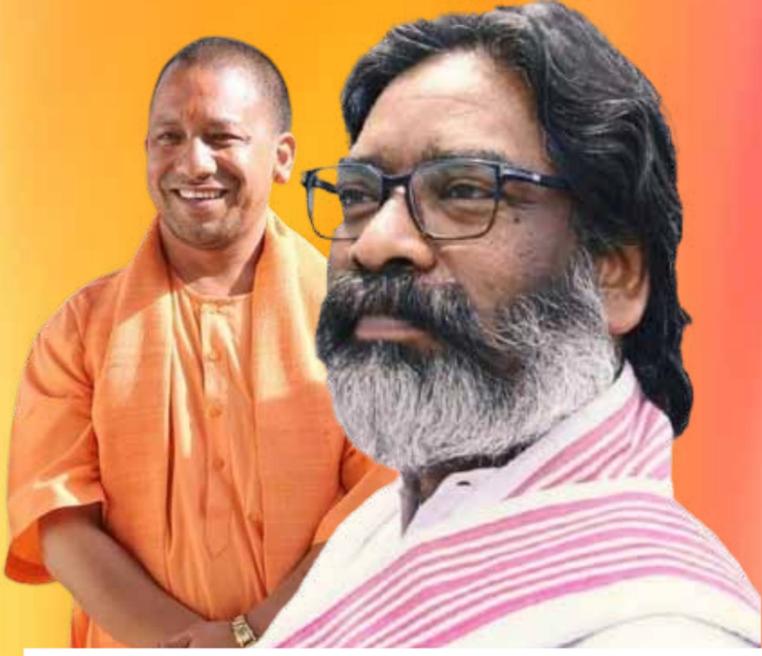


अमोद निराला
अध्यक्ष

पहली वर्षगांठ
पर पूरी टीम को
हार्दिक बधाई

प्रदेश सरपंच संघ, बिहार

मुखियाजी ईपेपर



के कदम अब झारखंड और उत्तर प्रदेश की ओर



हेमंत
और योगी
सरकार
की रोचक
कहानियां
पढ़ें
मुखियाजी
डॉट कॉम
पर भी



QR Code को
स्कैन कर पढ़ें
पंचायत की खबरें

चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त भी हैं नीतीश कुमार

Rajesh Thakur @ Patna

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार को लेकर समाजवादी वाला बयान तब आया था, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना था। इसी बयान से उन्होंने यूपी के साथ ही बिहार पॉलिटिक्स को भी साधने का काम किया था। दरअसल, उस समय बीजेपी को जहां यूपी में चुनाव को लेकर टेंशन था, वहीं बिहार में 'योगी मॉडल' को लेकर बीजेपी के कुछ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे थे। इसकी परिणति भी देखने को मिली, जब नीतीश कुमार एनडीए को झटका देते हुए महागठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि, यह सियासी संबंध भी बहुत दिनों तक नहीं चला और वे फिर से एनडीए के साथ हो गए। सियासी पंडितों की मानें तो नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में सियासी समीकरण को बैलेंस करने आता है। उनमें चाणक्य के साथ ही चंद्रगुप्त के भी गुण हैं। वे बिहार ही नहीं, देश की सियासत के भी माहिर खिलाड़ी हैं। वे किस समय, कौन-सा कदम चलेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन कोई कदम फालतू या बेवजह नहीं होता है। विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसके बाद भी उनकी सियासी ताकत का अंदाजा राजद को भी काफी अच्छे से पता है और बीजेपी को भी, साथ ही बाकी पार्टियों को भी। भाजपा जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रट लगाए हुए है, उसी ताकत का नतीजा है। अगर लोकसभा चुनाव के एनवक्त पर यदि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आते तो फिर यूपी की तरह बिहार में भी भाजपा की हालत पतली हो जाती। इतना होने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बिहार में 9 सीटों का घाटा हुआ था।

क्या कहती है वो तस्वीर

आपको याद होगा, दो-दो-दो माह पहले निशांत कुमार का मीडिया में बयान आया था कि एनडीए उनके पिता के नाम को इस साल होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। इसके ठीक 2-3 दिन बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक बयान में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर, यह भी सवाल बार-बार उठ रहा है कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? तो होली के मौके पर जारी फोटो से बड़े-बड़े दिग्गजों को अघोषित रूप से जवाब मिल गया होगा। फोटो में बांयो ओर जदयू के

कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं तो बांयो ओर बिहार सरकार के जदयू कोटे से बने सबसे वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी हैं। बीच में निशांत कुमार। फोटो का पोज देखकर सियासी पंडितों को भी समझ में आ गया कि जदयू को 'उत्तराधिकारी' मिल गया है। उन्हें सियासी मंड्यार में 'नाव' की तरह धीरे-धीरे उतारा जा रहा है, ताकि पार्टी के सहयोगी और विरोधी भी बैलेंस में रहे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि निशांत की अघोषित रूप से राजनीति में पंटी हो गयी है। बस, इसका ऐलान होना रह गया है। कुछ लोग तो पोस्टर के जरिए उन्हें 'धन्यवाद' भी देने लगे हैं।

अब बस ऐलान का इंतजार

बहरहाल, निशांत ने पिछले दो-दो-दो माह में बारी-बारी से मीडिया से बात करते हुए जिस तरह अपनी राय रखी और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से चुनाव में जिताने की अपील की है, उससे साफ पता चलता है कि निशांत अब पहले से काफी बदल चुके हैं। वे परिपक्व होते जा रहे हैं। लेकिन, निशांत के राजनीति में आने का

ऐलान कब होगा, उनका पार्टी में क्या रोल होगा, उन्हें कौन-सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारे सवालों के जवाब पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन, जिस अंदाज से उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को लेकर जवाब दिया कि वो तो मेरे अंकल हैं, सियासी पंडितों को 'चिंतन-मंथन' करने के लिए विवश कर दिया है...

सियासी पंडित भी अब मानने लगे

यहां हम बात कर रहे हैं निशांत कुमार के राजनीति में पंटी की। कहा जाता है कि नाविक नयी नाव को मंड्यार में धीरे-धीरे उतारता है। उन्हें पता रहता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। कुछ ऐसा ही निशांत कुमार के साथ भी हो रहा है। उन्हें बिहार के सियासी मंड्यार में बैलेंस बनाने हुए धीरे-धीरे उतारा जा रहा है। इस बार अंदर से नीतीश कुमार के निकट रहने वाले कई दिग्गज नेताओं का भी साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर कुछ ऐसी तस्वीरें

सामने आयीं, जिससे इसका भी साफ संकेत मिला कि

निशांत के साथ उनके पिता नीतीश कुमार

और उनके साथ निशांत काफी मजबूती

के साथ खड़े हैं। पिता-पुत्र की स्ट्रॉंग

बॉन्डिंग से निशांत की पॉलिटिकल

पंटी को भी सहजता से समझा जा सकता है। सियासी पंडित तो यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा को दो बार राजद के सहयोग से बैलेंस में रखा, यही फॉर्मूला उन्होंने हम पार्टी के संस्थापक जितनराम मंडी पर भी लगाया था। और अब, वे जदयू को बचाने के साथ ही भाजपा को भी बैलेंस में रखने की जुगत में हैं। सियासी पंडित यह भी मानते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार और निशांत कुमार की फोटो में बॉन्डिंग दिखी, उसका साफ संदेश है कि निशांत अपने पिता के लिए हमेशा ढाल बनकर मौजूद रहेंगे और जल्द ही उनकी राजनीति में पंटी होगी। हाल ही में निशांत का बयान आया था कि उनकी अमित अंकल (अमित शाह) से बात हो गयी है। उनके पिताजी ही बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि वे अपने पिता के लिए कितनी मजबूती से खड़े हैं।



सियासी बगीचे में खूब
फल-फूल रहे हैं
ये पौध

बिहार की सियासत में पिछले एक दशक से नए पौध खूब फल-फूल रहे हैं। कुछ तो 2015 में ही विधायक बन गए। कुछ सांसद भी बने हैं। 2015 के चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव राजनीति के मैदान में आ गए। इससे पहले उनकी बड़ी बहन मीसा भारती आर्यो। पहले राज्यसभा और अब लोकसभा पहुंच गयीं। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं। 2014 में पहली बार सांसद बने थे। इस बार वे लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इसी तरह, अपने समय के चर्चित सांसद रहे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आज शिवहर से विधायक हैं। चेतन की मां लवली आनंद शिवहर की ही वर्तमान सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह भी उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटा दिव्या प्रकाश तो चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैदान में और भी कई नेताओं के बेटे-बेटा टिकट के इंतजार में हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि विस अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, जाप प्रमुख पप्पू यादव के बेटे भी चुनावी दौड़ में शामिल हैं। और रही बात वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तो शुरुआत में इन्हें भी विरासत का लाभ मिला, लेकिन बाद में ये अपनी मेहनत से एनडीए में खास जगह बनायी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विधान मंडल के नेता और उपमुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं।



20 मई को वामदलों की ओर से बुलाये गए बंद को महागठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी समर्थन देने का निर्णय लिया है...

सीटों पर एक कब तक होंगे

Rajesh Thakur @ Patna

भा जपा के ये दो नारे पिछले दिनों उनके समर्थकों में काफी प्रचलित हुए थे। ये नारे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विशेषतौर पर दिए गए थे। पहला- हम एक हैं तो सेफ है, दूसरा- बंटोगे तो कटोगे...। इसे लेकर सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक पर काफी दिनों तक हलचल मचा रहा। यहां तक कि इस पर पैरोडी सांग भी सियासी मार्केट में आ गया। दरअसल, भाजपा ने ये नारे हिंदुत्व एजेंडा को मजबूत करने के उद्देश्य से दिए थे। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खूब को मजबूत करने के लिए इन नारों को अब महागठबंधन अमलीजामा पहना रहा है। 4 मई को पटना में हुई बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दलों ने एक सुर में कहा, 'हम सब एक हैं।' महागठबंधन में किसी तरह को कोई विवाद नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सीटों के बंटवारे पर एक कब होंगे?

पटना में महागठबंधन की इस साल यह तीसरी संयुक्त बैठक हुई। इसके पहले हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोडिनेशन कमिटी का नेता चुना गया था। तब सियासी गलियारे को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम उम्मीदवार के रूप में मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महागठबंधन की तीसरी बैठक में भी इस पर कोई ठोस डिसेजन नहीं हुआ। हालांकि, सियासी पंडितों की मानें तो भले ही देर हो रही हो, लेकिन अंततोगत्वा सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर मुहर लगनी तय है। मुखियाजी ईपेपर के 54वें अंक में 'सीएम फेस' पर प्रमुखता से स्टोरी छपी थी। लेकिन, महागठबंधन के लिए असली टैशन सीटों का बंटवारा है। वर्तमान में महागठबंधन में 6 दल हैं। राजद, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के अलावा वामदलों के तीन घटक दल। इनमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-माले हैं। इसी महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा भी शामिल होने की फिराक में है।

पटना में 4 मई को हुई बैठक के बाद राजद सांसद मनोज झा ने मीडिया को बताया कि महागठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है। हमारे बीच बेहतर तालमेल है। महत्वपूर्ण यह है कि महागठबंधन में समन्वय से संवाद है। हम

सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर रहे हैं। महागठबंधन ने केंद्र और राज्य सरकार की स्वामियों को उजागर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला से पंचायत स्तर तक संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। यही नहीं, महागठबंधन ने यह भी तय किया है कि इस साल होनेवाले विधानसभा चुनाव में साझा प्रचार किया जाएगा। साथ ही संयुक्त रूप से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। चुनाव प्रचार को एकजुटता के साथ रणनीति बनाकर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे दबाव के कारण ही जाति जनगणना को जहर बताने वाले अब इसके लाभ बताने को विवश हो रहे हैं।

बहरहाल, लगभग साढ़े तीन घंटे चली महागठबंधन की तीसरी बैठक में सभी घटक दलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी व जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। सबों ने एक स्वर में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। 20 मई को वामदलों की ओर से बुलाये गए बंद को महागठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी समर्थन देने का निर्णय लिया है। घटक दलों में जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय कायम करने के लिए राज्य से लेकर जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर तक समन्वय से संवाद कार्यक्रम चलाएगा। लेकिन, इसमें न तो सीएम फेस पर कोई चर्चा हुई और न ही सीटों के बंटवारे पर ही कोई संकेत मिला। सियासी पंडितों की मानें तो कांग्रेस 2020 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो कांग्रेस की ओर से 100 सीटें लेने की मांग कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे पर आनेवाले दिनों में घटक दलों का क्या रुख होता है।



कांग्रेस कम से कम 100 सीटों पर लड़े

इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 100 सीटें मिलनी चाहिए। यह कहना है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद व जपा प्रमुख पप्पू यादव का। उन्होंने रविवार को पटना में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। उन्होंने कांग्रेस की तरफदारी करते हुए कहा कि यह समय की मांग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2025 चुनाव में एनडीए गठबंधन हर हाल में पराजित होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने अपनी पार्टी जपा के कांग्रेस में विलय को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के सभी नेता सहमत हैं। हमारा हर प्रयास कांग्रेस की मजबूती के लिए है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कि उनकी पार्टी और कांग्रेस जल्द ही पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा।

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

महागठबंधन में चेहरा को लेकर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अभी इसमें जो चेहरा है, वह बाद में भी रहेगा। लेकिन एनडीए में जो अभी सीएम हैं, वे चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। 20 मई को इंडिया गठबंधन के लोग मजदूरों के साथ सड़क पर उतरेंगे। इसके पहले 18 मई को प्रदेश, जिलास्तर पर घटक दल के अध्यक्ष, प्रभारी एक साथ बैठेंगे और प्रखंड व पंचायत स्तर पर समन्वय बनाने को लेकर चर्चा करेंगे।

कृष्णा अल्लावारू, बिहार प्रभारी, कांग्रेस

एनडीए झूठ फैला रहे हैं, हम लोगों को सच बताएंगे। महागठबंधन मजबूत है, एनडीए मजबूर है। हम मजबूत इसलिए हैं कि जातीय जनगणना का मसला हमने उठाया और वे इसे लागू करने को मजबूर हुए। हम बूथ स्तर तक बेहतर समन्वय बनाएंगे। बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। लोकतंत्र में लोक हमारे साथ है, उनके साथ केवल तंत्र बच गया है। हमलोगों में कोई विवाद नहीं है।

सियासी गलियारा

विकासित भारत



बिहार के भाजपा विधान पार्षद जीवन कुमार शनिवार को देहरादून में थे। उन्होंने IT पार्क में बिहारी मूल के बिजनेस संचालकों के संग विकासित भारत पर विस्तृत चर्चा-परिचर्चा की।



विरोध प्रदर्शन

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बिहार में सियासत अभी भी तेज है। इसी कड़ी में शनिवार को वक्फ के विरोध में पटना में भाजपा-माले के बैनर तले 'इसाफ मंच' ने किया प्रदर्शन।



आत्मीय मुलाकात

झारखंड के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भेंट की। उनके साथ गोविंदाचार्य भी मौजूद थे। श्री राय ने कहा, इससे पुरानी स्मृतियां ताजा हुईं।



कार्यक्रम

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 15 मई को बिहार पहुंचे। दरभंगा में दलित छात्रों से मुलाकात की। फिर पटना में लोगों के साथ बैठकर सिनेमा देखे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, रिसर्च टीम के आनंद माथव, डॉ मधुबाला सहित अन्य लोग शामिल रहे।



हाथ में मुखियाजी

मुखियाजी ईपेपर का 55वां अंक पाठकों को खूब पसंद आया। इसका प्रिंट निकाल कर पढ़ रहे हैं भाजपा नेता प्रवीण राय। साथ में अपने सहयोगी राजीव मिश्रा के साथ विमर्श भी कर रहे हैं।



Rajesh Thakur @ Patna

म शहर सिंगर अल्ताफ राजा का 1998 में गया एक गीत देश-दुनिया में काफी प्रचलित हुआ था। गीत के बोल थे- तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे... इसी गीत में आखिर के बोल थे- 'वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है...' यह बोल आज भी सुपर-डुपर हिट है। और, यहां प्रसंगिक भी है। यह प्रसंग इस बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई 'लड़ाई' पर लागू हो गया। सच में वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल 1971 का था और ये साल 2025 का है। पांच दशक से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। 54 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के रंग-रंग में जो 'आतंकी' हरकत कूट-कूट कर भरी थी, उसमें और अधिक इजाफा ही हो गया है। हरकत और भी बढ़ से बढ़तर ही हो गयी है। इस दरम्यान पाकिस्तान में कितनी ही बार सत्ता परिवर्तन हुआ। कभी लोकतंत्र के जरिए सरकार बनी तो कभी सेना की तानाशाही सरकार बनी। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बदलते रहे। लेकिन नहीं बदली तो उसकी घटिया हरकत। इस बार पाकिस्तान सीजफायर तो करा लिया, लेकिन किसी भी भारतीय को उसकी कथनी पर कतई भरोसा नहीं है। बिहार में भी हर कोई इस फैसले से हतप्रभ है। लोगों को आयरन लेडी के नाम से ख्यातिलब्ध देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अचानक याद आने लगीं।

लेकिन, इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान की 'थर्ड ग्रेड' चाल-चलन में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वह आतंकवाद को समर्थन देने से बाज नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, अब तो वह बच्चों की भी जान ले रहा है। महिला-बच्चों के पीछे छिपकर वार कर रहा है। निरीह लोगों की आड़ लेकर ड्रोन से हमला कर रहा है। 9 मई को लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बॉर्डर से सटे 15 शहरों के 36 स्थानों पर लगभग 400 ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया। भारत ने सबों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने हमारी सीमा के अंदर आम नागरिकों को निशाना बनाया। महिलाओं और बच्चे उसकी चपेट में आए। पूंछ के इलाके एक दर्जन से अधिक आम लोगों की जान गयी। दो बच्चे भी मारे गए। ख़ास बात कि उसने इस दौरान न अपने बॉर्डर इलाकों के बाजार ही बंद किये और न ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को ही रूक किया। इसी बीच, 10 मई को अचानक समाचार आने लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर के लिए मध्यस्थता की है। अमेरिका का एक्स अकॉउंट पर पोस्ट आ गया कि उसने भारत और पाकिस्तान को इसके लिए खूब समझाया, तब जाकर दोनों तैयार हुए। इसके तुरंत बाद भारत सरकार का बयान आया कि वह सीजफायर पर राजी हो गया। इससे पाकिस्तान की जनता तो काफी खुश है, लेकिन भारत की जनता काफी मायूस।

आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज नहीं आ रहा है।



क्यों याद आ रही हैं इंदिरा गांधी

भारत और पाकिस्तान के बीच महज पांच दिनों में ही जिस तरह सीजफायर हो गया, उससे 1971 की लड़ाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां के लोगों को याद आने लगी हैं। जिस दिन सीजफायर का ऐलान हुआ, उसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के टॉप टेन ट्रेंड में इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगी थीं। शनिवार की देर रात तक एक लाख से अधिक पोस्ट इंदिरा गांधी को लेकर किये गए थे। फेसबुक पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। लोग उनकी शहादत को भी याद कर रहे थे और 1971 की जंग की दुहाई दे रहे थे। दरअसल, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 93 हजार पाक सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी पर उस समय भी अमेरिका का काफी दबाव पड़ा था, यह दबाव आज से काफी अधिक था, लेकिन उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यह भी सच है कि यदि आज पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश नहीं बनता तो वह और भी दोगुनी ताकत से भारत के खिलाफ खड़ा रहता। यही वजह है कि यहां के लोग चाह रहे हैं कि ब्लूचिस्तान अलग हो जाए।

ट्रंप पर क्यों चुप हैं नरेंद्र मोदी

हालांकि, युद्ध से भारत के लोग भी खुश नहीं थे, किंतु वे इतना जरूर चाहते थे कि पाक को सबक मिले। भारत के लोगों की पहली इच्छा थी कि POK (पाक अधिकृत कश्मीर) फिर से भारत का हिस्सा हो। वह भारत का अंग हो। वे यह भी चाहते थे कि पाक से ब्लूचिस्तान को आजादी मिल जाए। वहां की जनता ने विद्रोह शुरू भी कर दिया था और वह भारत की ओर मदद मिलने की उम्मीद से टकटकी लगाए हुए था। साथ ही भारत के लोगों की यह भी इच्छा थी कि कुख्यात आतंकवादियों को पाक सौंप दे। किंतु कहा जाता है कि अमेरिकी 'दादागिरी' ने सब खेल बिगाड़ दिया। सबसे बड़ी बात कि बिहार की धरती से पाकिस्तान को खुली चुनौती देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रकरण पर लगभग 50 घंटे चुप रहे। फिर 12 मई की रात 8 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में अपनी बातें रखीं। पीएम ने कहा, भारत ने लड़ाई स्थगित की है, बंद नहीं। पाक की ओर से यदि कुछ होता है, तो इसका जवाब और भी कड़ा व विनाशकारी होगा। लेकिन, ट्रंप को लेकर वे कुछ नहीं बोले। बहरहाल, लोगों को यही शिकायत है कि अमेरिका बीच में 'दादागिरी' दिखाए आखिर क्यों आया ?

RIP

**2004 में हुए
उपचुनाव में जदयू
के टिकट पर उन्होंने
पहली बार जीत
हासिल की।**

नहीं रहे पूर्व मंत्री आरएन सिंह

परबत्ता विस क्षेत्र से 5 बार बने थे MLA

सरकारी नौकरी छोड़ आए थे राजनीति में

विधानसभा कैंपस में दी गयी अंतिम विदाई

बि हार के पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह नहीं रहे। शनिवार की रात उन्होंने पटना के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 85 साल के थे। उनके निधन की खबर से परबत्ता विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गयी। वर्तमान में उनके एक पुत्र विधायक तो दूसरे पुत्र विधान पार्षद हैं। रामानंद सिंह बिहार की सियासत में आरएन सिंह के नाम से लोकप्रिय थे। वे खगड़िया के परबत्ता विधान सभा क्षेत्र से 8 बार चुनाव लड़े थे, जिनमें 3 बार हारे थे, जबकि 5 बार विजयी हुए थे। वे 1995 में राजनीति में आए थे और क्षेत्र में लगभग द्वादशकों तक राजनीति की धुरी बने रहे।

स्वर्गीय आरोग्य सिंह के पुत्र रामानंद ने 1967 में यूनाइटेड किंगडम की लीड्स यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर के पद से इस्तीफा

देकर 1995 में राजनीति में कदम रखा। पहली बार 1995 में रामानंद सिंह ने भाजपा के टिकट पर ही पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दूसरे स्थान पर रहे। 2004 में सम्राट चौधरी की सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में जदयू के टिकट पर उन्होंने पहली बार जीत हासिल की। 2005 में फरवरी और अक्टूबर के चुनावों में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। 2008 में उन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाया गया। 2010 में हार का सामना करने के बावजूद, 2014 के उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार वापसी की। स्वास्थ्य कारणों से 2020 में वे चुनाव नहीं लड़े। उनकी जगह उनके पुत्र डॉ. संजीव कुमार चुनाव लड़े और किसी तरह 951 वोटों से जीते। उनके दूसरे पुत्र राजीव कुमार वर्तमान में एमएलसी हैं।

सियासी गलियारे में शोक की लहर



पूर्व मंत्री आरएन सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विस अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अनेक मंत्रियों, विधायकों, विधान पार्षदों ने शोक प्रकट किया। उधर, दिवंगत पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर उसी दिन बिहार विधानसभा परिसर लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर पर अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात्

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जयंतराज, तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, पूर्व विधायक मनोज शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा बिहार विधानसभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान परबत्ता से विधायक एवं उनके पुत्र डॉ. संजीव कुमार एवम् अन्य पारिवारिक सदस्यों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



भाजपा के वरिष्ठ नेता
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद

श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी

की पुण्यतिथि पर
भावपूर्ण श्रद्धांजलि



सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री, बिहार सरकार

[f @samratchoudharyofficial](https://www.facebook.com/samratchoudharyofficial) [@samrat4bjp](https://twitter.com/samrat4bjp) [samratchoudhary.in](https://www.samratchoudhary.in)



Bro के अटपटे सवाल

Grok के चटपटे जवाब



इंसान में भेड़िया वाला गुण कहां से आया?

सवाल : कुत्ता, गधा, बैल सब में अपना-अपना गुण है, ये सब गुण एक साथ इंसान में मिलता है। अब तो इसमें भेड़िया वाला गुण भी आ गया कैसे?

राजीव, रामपुर-श्यामचक, राधोपुर

जवाब : अरे, राजीव जी, ये सवाल तो जंगल में तहलका मचा देगा! सही कहा, भेड़िया जंगल का वो शरक्स है, जिसे लोग चालाक, धोखेबाज, और 'सब मेरा' वाला मानते हैं। आजकल इंसान में भी यही दिखता है। कोई ऑनलाइन स्केम करता है, कोई ऑफिस में फ्रेडिट हड़प लेता है, कोई सरेआम लड़कियों और महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी इज्जत लूट रहा है। यह सब देखकर तो मुंह से पहला वाक्य यही निकलता है, 'अरे, ये तो पक्का भेड़िया है!' हालांकि, भेड़िया में भी कुछ इंसान वाला गुण है, मसलन, जंगल में भेड़िया अपने दोस्तों के लिए जान लड़ाता है, रात-रात भर जागकर अपने इलाके की हिफाजत करता है। लेकिन, इंसान अपनी इंसानियत छोड़, अन्य पशुओं के साथ भेड़िया वाला गुण कुछ ज्यादा ही अपना लिया है। इन सबके पीछे सिर्फ लालच होता है। लालच में पड़कर इंसान गलत रास्ते पर कदम बढ़ा देता है। इंसान अपनी अहमियत समझे और सही राह पर खुद भी चलें और दूसरों को भी चलने की प्रेरणा दें। अगले हफ्ते का सवाल और भी मजेदार होगा। आप क्या पूछना चाहेंगे? अपने सवाल 950777555 पर व्हाट्सअप करें।

कविता कॉर्नर

सुहाना डगर

सुहाना डगर है।
अंजाना सफर है।।

सचमुच पता नहीं
कि जाना किधर है।

निगाहें हैं कहीं
निशाना इधर है।

बहम है नजर को
ठिकाना जिगर है।

सुकून यहां कहां
खचाखच शहर है।

हवा भी क्या करे
जहर ही जहर है।

कयामत आएगी
जहां बेखबर है।



ज्योतिष चंद्र

तू कौन

जात है भाई!

जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के निर्णय के बाद बिहार में सियासत बहुत तेज है। यहां एनडीए और इंडिया महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच इस फैसले के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कोई पटाखा फोड़ रहा है तो कोई लड्डू बांट रहा। दरअसल, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो समय-समय पर सियासी गलियारे को गरम कर दे रहा है। चुनावी साल की वजह से जातीय जनगणना के मुद्दे को हर राजनीतिक दल लपकना चाह रहा है। सियासी सूत्रों की मानें तो एक समय था, जब भाजपा और कांग्रेस इस जनगणना के प्रबल विरोधी थे, लेकिन वर्तमान में दोनों बड़े दल हितैषी हो गए हैं। वहीं राजद तो एक कदम आगे बढ़कर काफी उत्साहित है। इन सबसे हटकर जानते हैं कि जातीय जनगणना के फायदे क्या हैं? 5 प्रमुख फायदों पर एक नजर...

Rajesh Thakur @ Patna

कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना। इसे लेकर ही इस चुनावी साल में इन दिनों बिहार में कुछ ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है। हर तबका जानना चाहता है कि उनकी जाति की सही स्थिति क्या है। खासकर कास्ट सेंसस के बारे में वह समाज या समुदाय तो हर हाल में जानना चाहता है, जिसकी आबादी अधिक है। इससे जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि समाज के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। समाज और सरकार को इस जनगणना से जातियों के सही डेटा का पता चलेगा।

फायदा नंबर 01

दरअसल, देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना के दौरान धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, आयु, लिंग आदि का जिक्र होता है, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का भी आंकड़ा लिया जाता है, लेकिन जाति आधारित आंकड़ा नहीं लिया जाता। ऐसे में मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। खासकर, ओबीसी यानि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों और उनकी जनसंख्या की सही स्थिति का तो जरूर पता चलेगा, जिसे लेकर कम्प्यूजन की स्थिति बनी रहती है।

फायदा नंबर 02

देश-दुनिया में कालांतर में कई जीव-जंतु विलुप्त हो गए हैं। इंसानों की कई जातियां-प्रजातियां समय व विकास के साथ खत्म होने के कगार पर हैं। वहीं जरूरत के अनुसार इंसान की कई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। खासकर स्थानीय जातियों में भी यह देखा जा रहा है। देश में उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। नयी पीढ़ी को तो अंगुली पर गिनती की दो-चार जातियों के अलावा अन्य जातियों के बारे में पता भी नहीं रहता है। दरअसल, नयी पीढ़ी जातीय जनगणना को फसाद से कम नहीं मानती है। झारखंड का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो स्थानीय समाज के बारे में लोग सही से जानते भी थे, लेकिन अब तो वह सब भी भूल जा रहे हैं। यही हाल मुस्लिम जातियों का है। हिंदुओं को तो शायद ही जानकारी हो कि मुस्लिमों में जाति-प्रजाति क्या होती है। कमोवेश यही स्थिति दलित-महादलित की भी है। कम-से-कम नयी पीढ़ी को तो नहीं ही पता होगा। ऐसे में जातीय जनगणना से विलुप्त हो रही जातियों-प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलेगी।

फायदा नंबर 03

केंद्र सरकार भले ही अब जाकर देश में जातीय जनगणना कराने पर राजी हुई है, जबकि बिहार में इसकी मांग लगातार हो रही थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले टर्म में जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था, तब जातीय जनगणना की ओर बिहार ने अपना निर्णायक कदम बढ़ा दिया था। सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश सरकार जातियों की गिनती करने में जुट गयी। इसके बाद सरकार ने अपने दम पर जातियों की न केवल गिनती कराई, बल्कि उन परिवारों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगवाया। कास्ट सेंसस से जुड़े एक्सपर्ट की मानें तो इससे बेशक वैसी जातियों-प्रजातियों को लाभ मिलेगा, जिनकी संख्या कम हो रही है। गणना से हाशिये और लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी जातियों या समुदायों का पता चलेगा, उन्हें बचाने और उनके उत्थान की पहल सरकारी स्तर पर की जा सकेगी। सरकार को सही निर्णय लेने में सहाय्य होगी। सामाजिक संगठन भी उनके अधिकारों के लिए सामने आएंगे।

फायदा नंबर 04

यह तो पूरा देश जानता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार सरकार की मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार एनडीए में ही थे। इसी मुद्दे पर राजद विरोध में रहते हुए भी जदयू के निकट आ गया था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती भी हुई थी। बाद में जदयू



महागठबंधन में शामिल भी हुए थे। यह अलग बात है कि वर्तमान में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में हैं। लेकिन, बिहार सरकार ने अपनी जिद और अपने खर्च पर राज्य में जातीय सर्वे कराया। हालांकि, इसे लेकर राजनीतिक स्तर पर विवाद भी चल रहा है, पर अब देश के स्तर पर जनगणना होने से सारे कम्प्यूजन दूर हो जाएंगे। सही डेटा सामने आयेगा। इस आधार पर सरकार कम से कम उन जातियों-प्रजातियों का सही से विकास करेगी, जो अब तक वंचित है। वंचित समाज का इसका सीधा लाभ मिलेगा। अन्य जातियों की स्थिति के आधार पर उनके विकास के लिए नीतियां बनायी जा सकेंगी। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस जनगणना से बेशक जातियों का विकास होगा।

फायदा नंबर 05

जातीय जनगणना का सबसे बड़ा लाभ आरक्षण में मिलेगा। हालांकि आरक्षण अब पूरी तरह सियासी मुद्दा हो गया है। विरोधी राजनीतिक दल बार-बार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते आ रहा है कि वह आरक्षण के खिलाफ है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह मामला उठा भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय यह मंडल कमीशन के रूप में जोरदार ढंग से उठा था। दरअसल, बिहार समेत पूरे देश में जाति के आधार पर नौकरी से लेकर स्कूल, कॉलेज तक में आरक्षण का प्रावधान है। जाति के आधार पर ही सियासी दल खड़े होते हैं और सत्ता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। खास कर बिहार और यूपी की राजनीति तो जाति के बिना अधूरी है। यही वजह है कि मैक्सिमम राजनीतिक दलों के सिर पर आरक्षण का भूत कुछ अधिक ही सवार रहता है। एक्सपर्ट की मानें तो जातीय जनगणना के पीछे आरक्षण बड़ा फैक्टर है। ऐसे में जनगणना से जातियों का आंकड़ा साफ होगा और वंचित समाज को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी जातियों को उनका हक मिलेगा।

